## दिनांक 26 जुलाई, 1985

सं. घो.वि./एफ.डी./143-85/31485.—चूंकि हरियाणाँ के राज्यपाल की राय है कि मैं गुरैरा गस सिलैंग्डर प्रा. लि., प्लाट नं. 133, सैक्टर-24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री किंशन बहादुर तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित भामले में कोई श्रीदोगिक विवाद है;

भीर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हैंतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, श्रोद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई क्वित्यों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए श्रधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त श्रधिसूचना की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते, हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत श्रथवा मंबंधित मामला है :---

क्या श्री किशन बहादूर की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. श्रो.वि./एफ़.डी./103-85/31492.--चूंकि हैरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. गुरैरा गैन सिलैण्डरस प्रा० लिं०., प्लाट नं० 133, सेक्टर-24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री श्री राम तिवारी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

श्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को त्यायनिर्णय हेत् निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं:

इसलिए, श्रव, श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई. शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415/3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए श्रिधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम+57/11245, दिनांक 7 फरवंरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदावाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनणेय के लिए निविष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री श्री राम तिवारी की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? सं. श्रो.वि./पफ.की./103-85/31499.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. गुरैरा गैस सिलण्डरस् प्रा० लि०., ण्लाट नं. 133, सैक्टर-24, फ़रीदाबाद, के श्रमिक श्री चुन्नी लाल तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई श्रोद्योगिक विवाद है ;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, भव, भौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रवान की नाई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20, जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-अम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदावाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री चुन्नी लाल की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं मो.वि./एफ.डी./103-85/31506.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. गुरैरा गैस निलैन्डरस प्रा० लि०., प्लांट नं० 133, सैक्टर-24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री शिवकुमार सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई मौद्यागिक विवाद है;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को त्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा अदान की गई मिन्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415—3—अम 68/15254-दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495-जी-अम—57/11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, फरीवाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिन्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रयन्धकों तथा अभिक्र के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद मे सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री-शिवकुमार सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?